आदिवासियों को अपनी जमीन के लिए हथियार उठाना पड़ेगा : गणेश घोघरा

डूंगरपुर का नाम डूंगरिया भील और माला कटारा के नाम करने की मांग उठाई

जयपुर (विसं)। विधानसभा में बुधवार को नगरीय विकास विभाग की अनुदान अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि आदिवासी कभी शहर की तरफ नहीं आया है, बल्कि शहर ही गांव की तरफ गया है और फिर कहते हो कि ''ये नक्सली है,'' अगर जरूरत पड़ी तो अपने अधिकार के लिए यह हथियार भी उठाएगा। अपनी जमीन के लिए आदिवासियों को हथियार उठाना पड़ेगा।

घोघरा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार का कोई मुख्य स्त्रोत नहीं है। आदिवासियों के पास एक और दो बीघा जमीन है। अपना जीवन यापन भी वे लोग मजदूरी करते हैं। घोघरा के इतना कहते ही बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई, जिस पर कुछ देर तक सदन में शोरगुल का माहौल बन गया।घोघरा ने कहा कि आदिवासी की छोटी जमीन भी कुछ लोग छीनना चाहते हैं। गेपसागर झील को नगर परिषद के आयुक्त और सभापति छीनना चाहते हैं। उन लोगों ने झील की जमीन पर प्लॉट काटकर भूमाफियाओं को बेच दिए। नाले का जो पानी आ रहा था, वह भी बंद कर दिया और प्लॉट काट कर बेच दिए। नगर परिषद डूंगरपुर में यह भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए।

घोघरा ने कहा कि डूंगरपुर का इतिहास डूंगरिया भील और माला कटारा के नाम से है। रात को माला कटारा का बोर्ड हटा दिया और वहां जय श्रीराम लिख दिया।

ऐसे में वहां कभी भी लोगों में आपस में संघर्ष हो सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। माला कटारा का बोर्ड वापस लगवाना चाहिए।

महिला विधायक को फटकार

जयपुर (विसं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को शून्यकाल में सदन में बात कर रहीं विधायक कल्पना देवी को फटकार लगा दी। बीजेपी विधायक को पहले तो स्पीकर ने धीरे से टोका, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। इस पर स्पीकर ने कल्पना देवी का नाम लेकर फटकार लगाई। दरअसल शून्यकाल में सदन की कार्यवाही के दौरान आपस में बात करने पर लाडपुरा विधायक कल्पना देवी को स्पीकर ने डांट दिया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, विधायक के पास जाकर समझाने लगे तो नेता प्रतिपक्ष ने फिर बातचीत को लेकर आपत्ति जताई। इस पर स्पीकर ने कहा कि वे तो उन्हें समझाने गए हैं।

सदन में सवाल पूछने की जगह लंबा ब्यौरा देने लगे निर्दलीय विधायक

स्पीकर ने टोकते हुए कहा, ''भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए''

जयपुर (विसं)। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को पूरक सवाल पूछने की जगह लंबा ब्यौरा देने पर निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी को टोकते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि, आप भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए।

निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी पूरक सवाल के दौरान कहा कि जबसे सरकार आई है, हमारे किसानों को पानी मिल रहा है। कांग्रेस राज में तो 5 साल पानी नहीं मिला। हमारे यहां नहरी तंत्र में बारिश का ओवरफ्लो पानी बेकार जाता है। स्पीकर ने टोकते हुए कहा कि सवाल पूछिए। यह भाषण हो रहा है। सवाल आप पूछ नहीं रहे। इस पर जीवाराम ने कहा कि आप इसे ही पूरक समझ लीजिए।

इस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यह बात सही है कि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पिछले दो साल में अच्छी बारिश हुई है। उनका पगफेरा राजस्थान के लिए शुभ है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसा तो रावत ने कहा कि मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा। रावत ने निर्दलीय विधायक जीपराम चौधरी के सवाल के जवाब में कहा कि नर्मदा नहर परियोजना पर टेल के किसानों तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या के समाधान के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। जब 1.96 करोड़ की डीपीआर बन जाएगी तो बरसात के वक्त ओवरफ्लो होने वाले पानी का रिजर्वेयर बनाया जाएगा।

पैंशन को लेकर हरिमोहन शर्मा ने मंत्री अविनाश गहलोत पर कसा तंज

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बकाया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले को लेकर बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पर तंज कसा। हरिमोहन शर्मा ने कहा कि सरकार ने 4 महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी, विधानसभा का सत्र चला तब बकाया पेंशन दी। खुशी की बात है, जिनके पास महकमे का चार्ज है, वह भी गहलोत है। एक गहलोत का तो सोच यह था कि किस प्रकार गरीबों का भला हो, दूसरे गहलोत का यह सोच कि चार महीने तक पेंशन भी नहीं दे। इसके अलावा जो नियमित रूप से पेंशन बढ़ानी चाहिए थी, उस हिसाब से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं बढ़ाई।

इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हमने पहले ही साल सामाजिक सुरक्षा एक हजार से बढ़ाकर 1150 किया, फिर 1200 किया, अब 1300 रुपए किया है।

वॉकआउट

जयपुर। सामाजिक संस्थाओं के जमीन आवंटन में देरी को लेकर शून्यकाल में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले कांग्रेस विधायक मोतीराम ने रेवदर में तीन समाजों को छात्रावास के लिए जमीन आवंटन में देरी का मुद्दा उठाया। मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि रेवदर में जमीन आवंटन के तीनों मामले पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के फैसले हैं। आज ये कह रहे हैं कि कमियां है अलॉटमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ राजनैतिक फायदे के लिए निर्णय किया।

सिरोही में छात्रावासों के लिए भूमि होगी आवंटित : राजस्व मंत्री

जयपुर (विसं)। राजस्व मंत्री ने विधानसभा में कहा कि जिले में विभिन्न समाजों के छात्रावास निर्माण के लिए नियमानुसार भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में नियमों की पूर्ण जांच-पड़ताल किए बिना ही भूमि आवंटन के निर्णय लिए थे, जिनमें लीज डीड सहित अन्य प्रशासनिक कमियां पाई गईं। इन कमियों के चलते प्रस्तावित आवंटन निरस्त कर दिए गए थे। राजस्व मंत्री ने आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार सभी प्रक्रियाओं की विधिवत जांच कर शीघ्र ही जमीन आवंटन की कार्रवाई शुरू करेगी। वे शून्यकाल के दौरान विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी नियम प्रक्रिया के तहत सामाजिक छात्रावासों के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन में देरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने शून्यकाल के दौरान सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले विधायक ने रेवदर क्षेत्र में तीन समाजों को छात्रावास हेतु भूमि आवंटन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया था।इस पर मंत्री हेमन्त मीणा ने कहा कि रेवदर के तीनों मामले पिछली सरकार के अंतिम छह महीनों में लिए गए निर्णयों से जुड़े हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट में फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली

इससे पूर्व भी 10 बार मिल चुकी है हाईकोर्ट को बम से उडाने की धमकी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। ई-मेल के जरिए दी गई इस धमकी में हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की की धमकी दी गई है। इससे पूर्व दस बार पहले भी यहां बम ब्लास्ट को लेकर धमकी भरे ई-मेल भेजे जा चुके हैं। मेल में धमकी दी गई कि 11 बजे तक हाईकोर्ट खाली कर दो, दोपहर डेढ़ बजे हाईकोर्ट में 18 बम धमाके होंगे। हालांकि अदालती समय आरंभ होने से पहले धमकी मिलने के चलते न्यायिक कामकाज प्रभावित नहीं हुआ और मुकदमों की सुनवाई शुरू होने के समय से पहले ही परिसर की जांच कर ली गई। मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।

इस पर दौरान जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की। जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन से राहत की सांस ली। आए दिन धमकी भरा मेल मिलने के बाद भी अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जिसके चलते वकीलों में खासी नाराजगी है। वकीलों का कहना है कि कभी यह धमकी वास्तविक घटना में बदल गई तो जान-माल का नुकसान हो सकता है। हाल ही में साइबर सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यशाला में भी हाईकोर्ट को दी जा रही बम ब्लास्ट का मुद्दा उठ चुका है।

सीजेआई सूर्यकांत की उपस्थिति में हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि जिस तरह स्कूल में रोजाना घंटी बजती है, उस तक हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकियां दी जाने लगी है। ऐसे में न्यायिक काम प्रभावित होता है, लेकिन यह ई-मेल कौन और कहां से कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन को सबसे पहले गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी। इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई। वहीं 8 दिसंबर से लगातार चार दिनों तक बम ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को ईमेल भेजे गए। इसके बाद गत छह फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी को ब्लास्ट की धमकी दी गई थी।

नए जिलों व तहसील के सवाल पर सदन में नोंकझोंक

जयपुर (विसं)। राजस्थान में नए जिलों और तहसील बनाने से जुड़े सवाल पर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कुछ देर के लिए सदन में हंगामे के हालात बन गए।

दरअसल कांग्रेस विधायक गीता बरवड़ के आसोप उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के मूल सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन और पुनर्गठन के लिए ललित के पवार कमेटी बनी हुई है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद नई तहसीलों पर फैसला होगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नए जिले को खालेंगे क्या? इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ''पिछली सरकार ने राजनैतिक लाभ के लिए नए जिले बनाए गए थे। जिले ले जाओ, तहसील ले जाओ और कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हमने लोगों की भलाई के लिए जिले-तहसील बनाए। आपने राजनीति करने के लिए बनाए।'' राजस्व मंत्री की इस बात पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए कहा कि आप बना नहीं सकते। आप तो तोड़ सकते हो। इसी बीच स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया तो हंगामा शांत हुआ।

महाराजा गजसिंह द्वितीय से मिला एफ.एच.टी.आर. प्रतिनिधिमंडल

जयपुर। फैडरेशन ऑफ होस्पेटिलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के नव-निर्वाचित अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने संघ के मुख्य संरक्षक एवं जोधपुर के महाराजा गज सिंह द्वितीय से शिष्टाचार भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल में एफएचटीआर से प्रेसिडेंट ऑनर भीम सिंह, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह पचार, उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह राठौड़, महासचिव मधुवंती सिंह व तरूण बंसल, कार्यकारी संस्थापक सदस्य सीए वीरेन्द्र सिंह शेखावत एवं कार्यकारी सदस्य दीपेन्द्र राणा उपस्थित रहे। बैठक में राजस्थान में पर्यटन के समग्र विकास एवं भविष्य की रणनीतियों पर सकारात्मक एवं रचनात्मक चर्चा हुई।

बैठक का प्रमुख विषय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2026 की रूपरेखा एवं रणनीतिक योजना रहा। प्रतिनिधिमंडल ने आरडीटीएम को भारत के अग्रणी घरेलू पर्यटन मंच के रूप में और अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने की अपनी दृष्टि साझा की। प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2026 में में एक विशेष ट्रैवल इवेंट आयोजित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस पहल का उद्देश्य ब्लू सिटी को विरासत पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग्स एवं सांस्कृतिक अनुभव आधारित पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रतिनिधिमंडल ने इस आयोजन को मारवाड़ की शाही विरासत, सांस्कृतिक संरक्षण एवं उत्कृष्ट आतिथ्य परंपरा के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए महाराजा गजसिंह द्वितीय से मार्गदर्शन का अनुरोध किया। अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा ने कहा कि महाराजा गज सिंह द्वितीय ने राजस्थान की अमूल्य विरासत के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक वैश्विक पर्यटन प्रवृत्तियों के अनुरूप आगे बढ़ने के महत्व पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

जयपुर में निजी बस ऑपरेटर्स के दो गुटों में टकराव, यात्रियों को जबरन नीचे उतारा

हड़ताल के कारण प्रदेश में दूसरे दिन भी थमे रहे प्राइवेट बसों के पहिए, 15 लाख यात्री प्रभावित

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हड़ताल का सीधा असर करीब 15 लाख से ज्यादा यात्रियों पर पड़ रहा है।

जयपुर,भीलवाड़ा, नागौर और उदयपुर सहित प्रदेशभर में निजी बस संचालकों ने न केवल अपनी बसें बंद रखीं, बल्कि लोक परिवहन की बसों को भी जबरन रोक दिया। राजधानी जयपुर में सुबह बसें चलाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। हड़ताल समर्थकों ने चल रही बसों से सवारियों को जबरन नीचे उतार दिया। वहीं उदयपुर में यात्रियों से भरी एक बस को रोककर उसके टायरों की हवा निकाल दी गई। भीलवाड़ा और नागौर में ऑपरेटर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।हड़ताल का सबसे ज्यादा असर खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है। इस मजबूरी का फायदा उठाकर टैक्सी संचालकों ने लूट मचा रखी है। यात्रियों का आरोप है कि जयपुर से खाटूश्याम (100 किमी) के लिए टैक्सियां 6 हजार रुपए तक की मांग कर रही हैं। एडवांस बुकिंग के बावजूद यात्रियों से अतिरिक्त पैसों की वसूली की जा रही है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने जयपुर पुलिस कमिश्नर सहित सीकर और जयपुर ग्रामीण के अधिकारियों को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। विभाग का दावा है कि लोक परिवहन के ऑपरेटर्स हड़ताल में शामिल नहीं हैं और वे बसें चलाना चाहते हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बस ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि यातायात सुचारू हो सके। निजी बस संचालकों का आरोप है कि परिवहन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से चालान काटे जा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऑपरेटर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और वे किसी भी सूरत में बसें नहीं चलने देंगे।

निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण जयपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो सका।

■ **जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर और उदयपुर सहित प्रदेशभर में निजी बस संचालकों ने न केवल अपनी बसें बंद रखीं, बल्कि लोक परिवहन की बसों को भी जबरन रोक दिया।**

पुलिस से सहमति के बाद वकीलों ने रास्ता खोला

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के बाहर गत 16 फरवरी से रास्ता रोककर बैठे वकीलों ने बुधवार शाम को पुलिस से समझौता होने के बाद धरना समाप्त कर दिया।

जयपुर (कासं)। शहर के निजी अस्पताल के संचालक के खिलाफ इलाज के दौरान लापरवाही करने को लेकर दर्ज एफआईआर में कार्रवाई की मांग के साथ गत 16 फरवरी से हाईकोर्ट के बाहर रास्ता रोककर बैठे वकीलों ने बुधवार शाम को पुलिस से समझौता होने के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल और डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज की ओर से संयुक्त जानकारी दी गई कि दोनों पक्षों के बीच सात बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसके तहत आरजीएचएस में अनियमिता के बारे में निविक अस्पताल से संबंधित जांच चिकित्सा विभाग की ओर से 20 दिन में पूरी कराने के संबंध में विभाग को पत्र लिखा जाएगा। वहीं जांच के बाद अपराध प्रमाणित होता है तो विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा। वहीं इलाज में लापरवाही को लेकर मानसरोवर थाने में दर्ज एफआईआर को लेकर परिवादी की इच्छा पर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए लिखा जाएगा। जांच एवं कार्रवाई पूरी होने तक अस्पताल को अस्थाई रूप से पैनल से बाहर करने के लिए आरजीएचएस को लिखा जाएगा। वहीं हाईकोर्ट में लंबित याचिका में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाएगी। वकीलों का समझौता हुआ है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीसीपी दक्षिण की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जाएगी और जांच एक माह में पूरी की जाएगी। वहीं केस की प्रगति के बारे में परिवादी को बताया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जांच में परिवादी शामिल रहेगा और हर सात दिन में बार एसोसिएशन को प्रगति के बारे में बताया जाएगा। वहीं समस्त दस्तावेजों व सीसीटीवी फुटेज की जांच एफएसएल से एक माह में कराई जाएगी।

डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से उतारा : टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष ने ईआरसीपी पर वादाखिलाफी और रिफाइनरी की अनदेखी पर सरकार को घेरा

जयपुर (विसं)। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के हालिया बयानों पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे प्रदेश की जनता के साथ क्रूर मजाक करार दिया है। जूली ने कहा कि भाजपा नेता जिन ऐतिहासिक दौरों का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनकी असलियत जनता जानती है।

जूली ने कहा, ''मदन राठौड आज उन वादों पर चर्चा करने से भाग रहे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की धरती से ईआरसीपी को लेकर किए थे। राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। आज अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए रामजल सेतु जैसे नए नाम गढ़े जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर प्यासे कंठों को पानी मिलना अब भी दूर की कौड़ी है।''

पचपदरा रिफाइनरी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर राज्य सरकार इसके उद्घाटन से क्यों कतरा रही है? मदन राठौड़ विकास की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या वे बताएंगे कि पचपदरा रिफाइनरी का काम पूरा होने के बावजूद उद्घाटन क्यों अटका हुआ है? क्या राज्य की भाजपा सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीख तक नहीं मिल पा रही है? रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चुप्पी और प्रधानमंत्री की बेरुखी यह साबित करती है कि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है, वे सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति में माहिर हैं। प्रदेश की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ रसातल में पहुँच गया है। लूट, हत्या और गैंगवार की बढ़ती घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेखौफ हैं और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

छह बदमाशों ने दो युवकों को घेरकर किया तलवार से हमला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भट्टा बस्ती इलाके में छह बदमाशों ने दो युवकों पर तलवारों और डंडों से हमला कर दहशत फैला दी। जान बचाने के लिए युवकों को नजदीकी घर में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पुलिस के अनुसार वारदात 23 फरवरी की है। वायरल वीडियो में बदमाश दो बाइकों पर सवार होकर युवकों का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं। मौका मिलते ही वे उन पर तलवार और डंडों से हमला कर देते है। आसपास के लोग जमा होते इससे पहले ही आरोपी फरार हो गए। भट्टा बस्ती थाना के थानाधिकारी दीपक त्यागी ने बताया कि अब तक किसी पक्ष की ओर से औपचारिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। हालांकि पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष एक ही समुदाय से जुड़े हैं और मामला आपसी रंजिश व पुरानी कहासुनी से संबंधित है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

■ **भट्टा बस्ती इलाके का मामला, जान बचाने के लिए युवकों को नजदीकी घर में शरण ली। इस दौरान 1 युवक गंभीर घायल हुआ**

'बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर मिलेगा अनुदान'

जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जिन नगरीय निकायों की सीमा और जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर ही अनुदान दिया जाएगा। प्रश्नकाल में विधायक कुलदीप द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री खर्रा ने बताया कि नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत करने के लिए परीक्षण कराया जाएगा और यदि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाया गया तो क्रमोन्नयन पर विचार किया जाएगा। इससे पहले विधायक कुलदीप के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रिश्वत के आरोपियों को जमानत नहीं

जयपुर। हाईकोर्ट ने आयकर अपीलीय अधिकरण में रिश्वत से जुडे मामले में आरोपी सीता लक्ष्मी, मुजम्मिल, राजेन्द्र सिसोदिया, विजय गोयल और कैलाश चन्द्र मीणा को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने इन सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह यह आदेश दिए। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद गत 4 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपी सीता लक्ष्मी की ओर से कहा गया कि वह अधिकरण में न्यायिक अधिकारी थी। ऐसे में जजेज प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं अन्य आरोपी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में न तो उन्होंने रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उनके कोई बरामदगी हुई है। इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। जिसकी सुनवाई लंबे समय तक चलेगी। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।

जिसका विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने कहा कि आरोपी पर रुपए लेकर फैसले देने का आरोप है। सीबीआई को गोपनीय सूचना मिली थी कि आईटीएटी जयपुर बेंच में लंबे समय से अपीलों को तय करने में धांधली चल रही है।